

रैपिडएक्स के स्टेशनों पर सुरक्षाकर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर हुए तैनात

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। रैपिडएक्स ट्रेनों का संचालन शुरू करने की तैयारियों के बीच एनसीआरटीसी ने दुहाई से साहिबाबाद के बीच प्राथमिक खंड के सभी स्टेशनों पर सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ की तैनात कर दी है। यह स्टाफ टिकट काउंटर पर बैठकर उसी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को टिकट और देने के दौरान ड्यूटी करनी है। इनके अलावा सुरक्षाकर्मियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है।

देश की पहली रीजनल रेल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एनसीआरटीसी की ओर से आधुनिकतम तकनीकों से लैस सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा रही है। यूपी सरकार ने इस कॉरिडोर में प्रदेश के सभी स्टेशनों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) को सौंपी है। इस सुरक्षा बल में तैनात सुरक्षाकर्मियों को ट्रेनिंग दे दी गई है। इसमें उन्हें सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी गई है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि स्टेशनों पर बने टिकट काउंटर पर भी स्टाफ को भी तैनात कर दिया गया है। उनका कहना है कि यात्रियों के लिए संचालन भले शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेनों को उसी तरह चलाया जा रहा है जैसे उद्घाटन के बाद चलाया जाएगा। पूरा स्टाफ निर्धारित ड्यूटी अवधि में काम कर रहा है।



इंडिया गठबंधन के नेताओं को देश नहीं, अपने परिवार की चिंता - नट्टा

साहिबाबाद। मेरी माटी-मेरा अभियान का शुभारंभ करने के लिए शनिवार को आए भाजपा अध्यक्ष जेपी नट्टा ने राजेंद्रनगर के मैदान और कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव और उद्धव ठाकरे को देश नहीं, अपने परिवार की चिंता है। इन सभी नेताओं के दल अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में लगे हैं।

उन्होंने कहा, मुंबई में इकट्ठा हुए लोग भ्रष्टाचार में आकंट डूबे हैं। कोई रेलवे की जमीन के बदले नौकरी के घपले में फंसा है तो कोई चारा घोटाले में। नेशनल हेराल्ड मामले में मां-बेटा (सोनिया-राहुल) जमानत पर हैं। आजकर मनीष सिंसौदिया कहाँ हैं, सबको पता है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, इन लोगों को दिल्ली से कोई मतलब नहीं। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति का पोषक बन गए हैं।

विपक्ष पर हमले के बाद उन्होंने मोदी सरकार की उपभ्रियां गिनाईं। बोले, जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 साल राज किया, आज पीएम मोदी के नेतृत्व में उसे पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। आटोमोबाइल



सेक्टर में देश जापान को पछाड़कर दुनिया में तीसरे और मोबाइल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहले मोबाइल मेड इन चाइना होते थे, आज मेड इन इंडिया फोन युवाओं के हाथ में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उत्पादन में लगभग 500 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हमारा निर्यात भी बढ़ा है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ये विकसित भारत के लक्षण हैं।

2जी से सिर्फ भ्रष्टाचार और जीजाजी आते थे याद

उन्होंने 2जी घोटाले का जिक्र करते हुए

करने के लिए आदित्य एल-1 का लॉन्च हो रहा है। इस बीच भारत माता की जय के उद्घोष से पंडाल गुंघा उठा। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री सांसद वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील बंसल, मेयर सुनीता दयाल, विधायक सुनील शर्मा मौजूद रहे।

शहीद मोहित शर्मा के घर से लेी मिट्टी

जेपी नट्टा ने राजेंद्रनगर में शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवार के सदस्यों से कलश में माटी लेकर मेरी माटी मेरा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, अभियान भारत का एक आह्वान है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर अमृत वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य देश के 140 करोड़ लोगों को साथ में जोड़ राष्ट्रभक्तों को याद करना और उनके बताए रास्तों पर चलना है। सरकार ने तय किया है कि हर गांव, वार्ड, पंचायत और ब्लॉक में जहां स्वतंत्रता सेनानी, पुलिस अधिकारी, सेना का जवान, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हों, उनको याद करना है। उनके नाम का शिलापट्ट लगाकर सम्मान करना है। मेजर मोहित शर्मा ने कुश्वाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते हुए देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।

शॉर्ट सर्किट से कार गैराज में लगी आग, बिल्डिंग में ऊपर तक पहुंची लपटें

परिवहन विशेष न्यूज

इंदिरापुरम। वसुंधरा सेक्टर-20 में गणपति रेजीडेंसी अपार्टमेंट के कार गैराज में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर गैराज में खड़ी कार भी जल गई। बिल्डिंग में ऊपर तक आग की लपटें उठने से लोगों के होश उड़ गए। आसपास दुकानों के लोगों ने बाहर की तरफ भागकर जान बचाया। अग्निशमनकर्मियों ने करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। इसमें कोई हानिहत्त नहीं है।

स्थानीय निवासी ने बताया कि गणपति रेजीडेंसी अपार्टमेंट में 32 फ्लैट हैं। भूतल पर बिल्डिंग मालिक ने दुकानें बनाकर किराए पर दी हुई हैं। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे कार मैकेनिक के गोदाम में कर्मचारी काम कर रहे थे। दुकान में एक कार भी खड़ी थी। कर्मचारी कार के पहिये खोल रखे थे। इस बीच अचानक

आग की लपटें तेजी से ऊपर उठने लगीं। किसी तरह मैकेनिक और कर्मचारी शोर मचाते हुए बाहर की तरफ दौड़े। अग्निशमन कर्मी ने बताया कि गैराज के गेट पर खड़ी क्रेटा कार के तुरंत दो शीशे तोड़कर उसे पोछे कर आग से बचाया। आग तेजी से फैलने पर अपार्टमेंट में धुआं भर गया। फ्लैटों में रहने वाले लोग सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़े तो कई लोग कमरे का दरवाजा बंद कर ऊपर छत पर पहुंच गए। परेशान और घबराए लोगों ने आग लगने के दौरान बिजली विभाग को फोन करके आपूर्ति बंद करा दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि सूचना पर वैशाली स्टेशन ऑफिसर कुंवर सिंह दो गाड़ियों लेकर टीम के साथ पहुंचे। कर्मियों ने आग पर जल्द काबू पा लिया। आग से सफल भी और दूसरी मंजिल के फ्लैट की बालकनी, दरवाजे व खिड़की पर लगे शीशे टूट गए।



महिंद्रा में ट्वीट किया एक वीडियो जिसमें लैंडर से उतरती दिख रही थार

आनंद महिंद्रा का अनोखा सपना, चांद पर उतारना चाहते हैं थार

परिवहन विशेष न्यूज

देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद्र महिंद्रा चांद पर अपनी थार-ई कार को उतारना चाहते हैं। महिंद्रा ने ट्विटर (एक्स) पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में लैंडर से थार-ई चांद की सतह पर उतरती दिख रही है।

नई दिल्ली। चांद के साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट लैंड कराकर भारत ने इतिहास रचा है। हमारे चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह से कई सारे डेटा जुटाए हैं। अब चांद पर रात होने वाली है, तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 14-15 दिनों के लिए सुला दिया गया है। इसरो ने बताया कि चांद पर रोवर ने अपना काम पुरा कर लिया है। इसे अब सफेक जगह पर पार्क कर स्लीप मोड में डाल दिया गया है। रात के बाद जब चांद पर दिन होगा, तो लैंडर और रोवर को फिर से चालू किया जाएगा। भारत के चंद्रयान-3 की सफलता ने भविष्य के लिए नए दरवाजे खोले हैं। उम्मीद है एक दिन ऐसा भी होगा जब भारत चांद पर ईसान को भेजेगा।

चांद पर थार उतारना चाहते हैं महिंद्रा

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) तो एक कदम आगे चल रहे हैं। वे चांद पर अपनी पॉपुलर कार थार-ई को उतारना चाहते हैं। महिंद्रा ने रविवार सुबह एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में एक छोटी सी वीडियो भी है। यह एक एनिमेशन वीडियो है, जिसमें चांद की सतह पर लैंडर से थार उतरती दिख रही है।

यह किया ट्वीट

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हमारी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए धन्यवाद इसरो। भविष्य में एक दिन हम चांद की सतह पर विक्रम और प्रज्ञान के बगल में थार-ई को उतरते देखेंगे और संभव को संभव करेंगे।' महिंद्रा के इस ट्वीट को बड़ी संख्या में लोगों ने लाइक और रिट्वीट किया है।

यूजर्स ने किये ये कमेंट्स

महिंद्रा की पोस्ट पर कई कमेंट्स भी आए। एक यूजर ने लिखा, 'सर आप जिस तरह से इसरो और उसके मिशन को प्रमोट कर रहे हैं, यह सराहनीय है। मुझे उम्मीद है कि और भी लोग आगे आएंगे और ग्रेट इसरो की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताते रहेंगे।' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं शर्त लगा सकता हूँ कि थार चांद पर काफी अच्छे से चलेगी।' कई यूजर्स ने महिंद्रा को उनके इस सपने के लिए शुभकामनाएं भी दीं।



मंडल स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी चयनित

गाजियाबाद। सुशीला बालिका इंटर कॉलेज में प्रथम क्षेत्रीय और जनपद कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। जूनियर वर्ग में अनमोल, सुभांशु, शिवम सिंह, अक्षित, हुमायरा, शिवांगी शिफा, इशु, कोमल और निशिका चयनित हुए। जूनियर बालक वर्ग में सुबोध, प्रियाशु, अर्पित, लक्ष्मण, मुकुल, यश त्यागी और बालिका वर्ग में वैष्णवी, डॉली शर्मा, यशवी सिंह, प्राची, अकांक्षा, प्राची साहू और रेनू चयनित हुईं। सीनियर बालक वर्ग में तनिष्क, मयंक, यश, नंदन कुमार, अमन और बालिका वर्ग में काजल भावना, जिया सिंह, मुस्कान अंसारी, सोनम विश्वकर्मा, तनिषा और शिवांगी का चयन हुआ। प्रतियोगिता में 150 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्य डॉ. अनुपम भारद्वाज ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

स्टंट करने वाले दो युवक गिरफ्तार, कार सीज

कौशांबी। पुलिस ने यूपी गेट के पास कार से स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को पकड़ लिया। दोनों हुंडई वर्ना गाड़ी से स्टंट कर रहे थे। दोनों की निशानदेही पर कार भी जब्त कर ली है। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कार से स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो कौशांबी का बताया गया था जिसमें दो-तीन युवक लापरवाही से कार चलाते हुए स्टंट कर रहे थे। लोगों की जान को खतरे में डालकर दोनों कार को जहां तहां रोक रहे थे। वीडियो के आधार पर उपनिरीक्षक रीगल कुमार की तरफ से मुकदमा कराया था। दोनों की पहचान हिमांशु और ऋतिक के रूप में हुई। गाड़ी हिमांशु चला रहा था। पृष्ठताछ के दोनों पर कार्रवाई की है।

प्रेमिका के परिजनों ने पीटा तो युवक ने फंदा लगाकर दी जान

लोनी। बॉर्डर थाना क्षेत्र के राहुल गार्डन कॉलोनी में एक युवक ने प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से नाराज होकर शुरुवार रात अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। मरने से पहले युवक ने अपनी बहन के फोन पर प्रेमिका के साथ के फोटो डाले थे। पिटाई में युवक घायल हुआ था। मृतक के परिजनों ने मामले में पुलिस को शिकायत की है। मूलरूप से हापुड़ में रहने वाले ललित कुमार (26) परिवार के साथ लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के राहुल गार्डन महेंद्र धामा एंक्लेव कॉलोनी में रहते थे। वह दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास मोटर मैकेनिक का काम करते थे। परिवार में बीमार मां प्रेमवती हैं। पिता सुदेश पाल की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी। जीजा लोकाेश ने बताया कि ललित करीब पांच साल से दिल्ली के सोनिया विहार कॉलोनी स्थित रहने वाली एक युवती से प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से मिलते थे। ललित युवती से शादी करना चाहता था। ललित ने बताया था कि उसने युवती की मांग में सिंदूर भर रखा था। बाद में युवती ने ललित से इन्कार कर दिया था। बुधवार को ललित दिल्ली में युवती से मिलने गया था। आरोप है कि युवती के परिजनों ने ललित के साथ मारपीट की। प्रेमिका के परिजनों की मारपीट से नाराज होकर ललित ने शुरुवार रात अपने घर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान परिजन घर में नहीं थे। परिजन जब घर पहुंचे, तो उन्हें घटना के बारे में पता चला। एसीपी रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।

इंस्टाग्राम का बनी निकला शाकिब, पहले से था शादीशुदा

कौशांबी। वैशाली सेक्टर-3 में 31 अगस्त की देर रात जिम रिस्पेसनिस्ट पंकी गुप्ता (23) की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। भाभी सोनी का कहना है कि शाकिब ने बनी बनकर पंकी से दोस्ती की थी। उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है। वह खुद को कुंवारा बताता था। घटना की रात उन्हें उसके शादीशुदा होने की जानकारी हुई। परिजन अब अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शनिवार को पंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें आत्महत्या की पुष्टि हुई है। वहीं, भाई शिवम ने पुलिस पर हत्या की तहरीर बदलवाने का आरोप लगाया है।

बदायूं जनपद के रहने वाले राजू गुप्ता की बड़ी बेटी पंकी गुप्ता वैशाली में जिम रिस्पेसनिस्ट का कार्य करती थी। चार साल पहले जिम में उसकी



जान-पहचान गाजीपुर के साकिब से हुई थी। दो महीने पहले पंकी वैशाली सेक्टर-3 में किराए पर रहने लगी थी। जबकि, शाकिब गाजीपुर में रहता था और उससे यहां मिलने आता था। भाई का आरोप है कि पिछले कुछ समय से शाकिब व उसका पिता उनकी बहन पंकी को बात-बात पर प्रताड़ित करते थे। दोनों आत्महत्या के लिए उकसाते थे। पंकी ने कई बार घर पर फोन करके मां और पिता को प्रताड़ना के बारे में बताया था। वहीं, भाभी सोनी ने आरोप लगाया कि शाकिब ने पंकी को अपना नाम बनी बनाया था लेकिन जब उन्हें बनी का धर्म और शाकिब नाम का पता चला तो उन्होंने पंकी को काफी समझाया था। पंकी ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह शाकिब से प्रेम करती थी। 30 अगस्त की रात पंकी का शाकिब से फोन पर झगड़ा भी हुआ था। तब पंकी ने यह बात उन्हें बताई थी।

राखी बंधवाने के लिए बहन के पास गए थे भाई-भाभी

सोनी के मुताबिक, रक्षाबंधन पर पंकी के पास दो भाई और भाभी गई थीं। तब भी उन्होंने पंकी को समझाया था। उस दौरान पंकी उन्हें कमरे में रोककर बात करना चाहती थी लेकिन वह मायके जाने की बात कहकर घर लौट आई थीं। उन्होंने पंकी से कमरे में मंदिर बनवाने के लिए भी कहा था। इतना ही नहीं, परिजन भी शाकिब को पसंद नहीं करते थे। आरोपी ने पंकी का ब्रेनवॉश कर दिया था। इस वजह से वह उनकी बात नहीं मानती थी।

डीसीपी शुभम पटेल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात आई है। मामले में आरोपी का गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। परिजनों के जो भी आरोप हैं उसकी जांच की जा रही है।

महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर चूल्हा जलाकर बनाया खाना

मोदीनगर। नगर के सीकरी खुर्द और आसपास की कई कॉलोनी की लगभग 18सौ बीघा जमीन को प्रशासन द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित करने के विरोध में तहसील मुख्यालय पर चल रहा ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 24वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर चूल्हा जलाकर खाना बनाया। वहीं शनिवार को एक प्रतिनिधिमंडल मेरठ सिवाल खस से विधायक गुलाम मोहम्मद की अगवाई में मेरठ मंडल आयुक्त सेहवा कुमारि जे से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने मंडल आयुक्त को विस्तार से बताया कि गलत तरीके से मोदीनगर की 18 सौ बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है।

प्रतिनिधिमंडल की ओर से मंडल आयुक्त को रालोद के मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी का शत्रु संपत्ति से संबंधित एक पत्र भी दिया गया। मंडलायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह एक सप्ताह के अंदर इस मामले की जानकारी कर इस समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शत्रु संपत्ति जन संसर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बबली गुर्जर, रालोद नेता डॉ. राजकुमार सांगवान, अमरजीत सिंह बिड्डी, रणवीर दहिया, अमित त्यागी और सत्येंद्र तोमर सहित कई शामिल थे। इधर तहसील मुख्यालय पर जारी धरने में क्रमिक अनशन पर शनिवार को पूनम देवी, रेखा, उषा, महेश और सोनू बैठे। महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर चूल्हा जलाकर खाना बनाया वहां मौजूद लोगों को खिलाया। अध्यक्षता शर्मा देवी और संचालन तिलकराज ने किया। इस अवसर पर ममता चौधरी, सतवीर प्रजापति, नीरज कौशिक, सुंदर गुर्जर, शकुंतला, सावित्री और मिथलेश आदि मौजूद थे।

नए नाम और लुक के साथ आ रही टाटा नैक्सॉन क्या बदलेगा और कितनी होगी कीमत, यहां जाने पूरी डिटेल

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी Nexon फेसलिफ्ट से पर्दा उठाया था. अब कंपनी Nexon को एक नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. इसे कंपनी Nexon.ev फेसलिफ्ट नाम से बाजार में उतारेगी. इसका डेब्यू 7 सितंबर को होने वाला है. नेक्सन से पहले .ev मोनिकर का इस्तेमाल टियागो ईवी के साथ कंपनी कर चुकी है. Nexon.ev में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे. कंपनी ने जो टीजर जारी किया है उससे पता चलता है कि कार में फुल विड्थ LED बार का इस्तेमाल हेडलाइट के तौर पर किया गया है. कार का फ्रंट Curvv कान्सेप्ट की तरह दिखता है. कार की बाकी डिजाइन भी काफी हद तक कर्व कान्सेप्ट जैसा ही लगता है.

सिंगल बाडी टोन कलर फिनिश
नेक्सन के इस माडल में आपको सिंगल बाडी टोन कलर फिनिश मिलेगी. वहीं इस कार के पेट्रोल वाले वेरियंट में कंट्रास्टिंग ब्लैक फिनिश दी गई है. टीजर में कार का रियर साइड भी दिखाई देता है. रियर यानी पीछे के हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कार में अलाय व्हील्स को नए डिजाइन के साथ पेश किया जा सकता है.

रेंज के लिए दो विकल्प
टाटा नेक्सन ईवी रेंज के लिए 2 विकल्प में उपलब्ध है. पहले इन्हें प्राइम और मैक्स नाम से सेल किया जाता है. अब इन्हें MR यानी मीडियम रेंज और LR यानी लान्ग रेंज नाम से सेल किया जाएगा. Nexon.ev में कोई मैकेनिकल बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. Nexon.ev MR 30.2kWh बैटरी के साथ जारी रहेगा और LR को बड़ी 40.5kWh बैटरी मिलेगी. MR की ARAI-अप्रूव्ड रेंज 312 किमी है, जबकि LR को रेंज 453 किमी (MIDC) है. MR में 129hp और 245Nm टॉर्क का आउटपुट होगा, जबकि LR में 143hp और 250Nm का आउटपुट होगा।



हुंडई जल्द ला सकती है Exter का इलेक्ट्रिक वर्जन, टाटा पंच ईवी से होगा मुकाबला



हुंडई ने जुलाई में अपनी Exter को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया था। इस कार को लोगों का काफी अच्छा रिसपॉन्स मिला। अब कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लाने जा रही है, जिसे टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा भी गया है। Exter EV मार्केट में टाटा पंच ईवी को टक्कर देगी।
पावरट्रेन
रिपोर्ट्स के अनुसार, Hyundai Exter EV में 25-30kWh बैटरी पैक दिया जा सकता है और ये लगभग 300 किमी - 350 किमी की रेंज देने में सक्षम हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

Ather 450S और 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में हुए लॉन्च, जाने कीमत, रेंज और फीचर्स

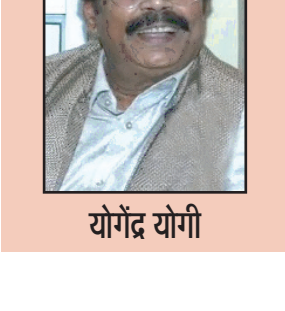
Ather launches three new 450 E scooters पहले की तरह इसमें एलईडी हेडलाइट और हैंडलबार काउल पर लगे टर्न इंडिकेटर्स मिलेगा। यहां तक कि इसकी बॉडीवर्क भी नए 450S और 450X के समान ही कॉम्पैक्ट है। हालांकि साइड लुक में थोड़े बदलाव को देखकर आप बदलाव देख सकते हैं। जो काफी अक्रामक अपील देती है। आइये इन तीनों वेरिएंट के कीमतों के बारे में जानते हैं।

एथर एनजी ने अपने लाइनअप में एक नहीं बल्कि तीन नए स्कूटर का अनावरण किया है, जिसे एक 450S और दो 450X के वेरिएंट शामिल हैं। हालांकि नाम अभी भी पहले जैसा है, लेकिन बैटरी पैक और फीचर्स में आपको फर्क दिखेगा। एक तरफ X अब अलग-अलग बैटरी और सुविधाओं के साथ दो वेरिएंट में उपलब्ध है। दूसरी ओर 450S एथर की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में आई है। आइए एथर 450 की तीनों मॉडल्स पर एक नजर डालें।
Ather लाइन अप में क्या हुआ बदलाव ?
नए बदलाव में पहले जैसी डिजाइन और लुक आपको देखने को मिलेगा। पहले की तरह

इसमें एलईडी हेडलाइट और हैंडलबार काउल पर लगे टर्न इंडिकेटर्स मिलेगा। यहां तक कि इसकी बॉडीवर्क भी नए 450S और 450X के समान ही कॉम्पैक्ट है। हालांकि साइड लुक में थोड़े बदलाव को देखकर आप बदलाव देख सकते हैं। जो काफी अक्रामक अपील देती है।
Ather 450 के तीनों वेरिएंट में क्या है अंतर ?
बैटरी पैक और रेंज में आप भिन्नता पाएंगे। एथर ने 450S को 5.4kW (पीक पावर) मोटर से जुड़ी 2.9kWh बैटरी से लैस किया है। इसमें मैक्सिमम 115 किमी की रेंज और 90 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड (तीनों मॉडल के लिए समान) मिलती है। Ather 450S को दो बैटरी विकल्प मिलते हैं, जिसमें 2.9kWh और 3.7kWh शामिल हैं। छोटी बैटरी 111 किमी की रेंज देने का दावा करती है और बड़ी यूनिट 150 किमी की रेंज देती है। हालांकि, दोनों केवल 6.4kW मोटर द्वारा संचालित हैं।
कितना लगेगा चार्जिंग टाइम ?
450S और 450X (2.9kWh) के लिए चार्जिंग समय आठ घंटे और 36 मिनट है जबकि 450X (3.7kWh) के लिए चार्जिंग समय पांच घंटे और 45 मिनट है।
Ather 450 प्राइस लिस्ट ?
एथर 450S की कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,29,999 से शुरू है जबकि 450X (2.9kWh) और 450X (3.7kWh) की कीमत क्रमशः 1,38,000 और 1,44,921 (सभी एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) है।



इसरो ने काफ़ी संघर्ष किया है तब जाकर अब सफलता का नया इतिहास लिख पा रहा है



योगेंद्र योगी

एक समय ऐसा भी

था जब संसाधनों

की कमी की वजह

से रॉकेटों को

बैलगाड़ी से भी ले

जाया गया था।

1981 में इसरो को

कम्युनिकेशन

सैटेलाइट के लिए

एक टेस्ट करना

था और पेलोड ले

जाने के लिए

बैलगाड़ी की मदद

लेनी पड़ी थी।

चंद्रयान तीन की सफलता की गुंज पूरे विश्व में सुनाई देर ही है। पूरे देश में दीवाली जैसा जश्न मनाया गया, किन्तु इस ऐतिहासिक सफलता के भी पीछे भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का ऐतिहासिक संघर्ष छिपा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिसकी उपलिब्धयों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, उसके वैज्ञानिक कभी साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट को लादकर प्रक्षेपण स्थल तक ले जाते थे। संघर्ष का ऐसा दौर इसरो के वैज्ञानिकों ने देखा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से ही रूस और अमेरिका स्पेस का सिकंदर बनने के लिए बेताब हो गए थे। दोनों देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। सबसे पहले 1957 में रूस ने अंतरिक्ष में कदम रखा। इसके बाद अमेरिका भी रूस के पीछे-पीछे चांद पर पहुंच गया। 1969 में अमेरिका ने अपोलो-11 मिशन पर 2 लाख करोड़ खर्च किए थे। जबकि मंगल तक जाने पर भारत को प्रति किलोमीटर 7 रुपए का खर्च आया था। आम तौर पर ऑटो का किराया इससे ज्यादा होता है, मंगलयान की लागत सिर्फ़ 400 करोड़ थी। चंद्रयान-3 की लागत मिशन इंपासिबल 7 की लागत का सिर्फ़ एक चौथाई यानि 25 फीसदी है।

भारत की अंतरीक्ष की दौड़ में आज जो सुनहरा वर्तमान देखने को मिल रहा है, उसकी संघर्ष की कहानी एक मिसाल है। अंतरीक्ष की इस दौड़ में भारत की विजय पताका लहरा रहे भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे दिन भी देखे हैं जब केरल के मछुआरों के गांव थुंबा की एक चर्च के आगे खाली जहाज से रॉकेट लॉन्च किया गया था। चर्च के विशप के घर को प्रयोगशाला बनाया गया था। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया था। हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था, वे कैथोलिक चर्च सेंट मेंी मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 13 सेंटर हैं कि किसी देश ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत एक दिन अंतरिक्ष में ऐसी उड़ान भरेगा जो सबके लिए मिसाल बन



जाएगी। उस समय देश में ट्रांसपोटेशन के पर्याप्त साधन तक नहीं थे। जिसकी वजह से रॉकेट के हिस्से को साइकिल की मदद से लॉन्चिंग की जगह पर पहुंचाया गया था। पहले रॉकेट के कुछ हिस्सों को साइकिल पर भी ले जाया गया था। एक समय ऐसा भी था जब संसाधनों की कमी की वजह से रॉकेटों को बैलगाड़ी से भी ले जाया गया था। 1981 में इसरो को कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए एक टेस्ट करना था और पेलोड ले जाने के लिए बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी थी। इसके अलावा भारत के पहले रॉकेट के लांच के समय भारतीय वैज्ञानिक हर रोज तिरुअनंतपुरम से बसों में आते थे और रेलवे स्टेशन से दोपहर का खाना खाते थे। केरल के थुंबा से पहला रॉकेट लॉन्च होने के 6 साल बाद डॉ. विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। भाकत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सर्वप्रथम 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय समिति

की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। बाद में सन्-1969 में डॉ. विक्रम साराभाई ने स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय राष्ट्रीय समिति के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की थी। डॉ. विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। 1971 में श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर बना था, जिसे आज सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर के नाम से जाना जाता है। अब यहीं से सभी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। 119 अप्रैल 1975 को इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। 1977 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो टीवी को गांव-गांव तक लेकर गया। इन्हीं मुश्किलों में हमारे वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी उपग्रह एसएलवी-3 लांच किया था। यह 18 जुलाई 1980 को लांच किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। इस लांचर के माध्यम से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। 1981 में इसरो का पहला

कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। जब कारगिल युद्ध में दुश्मन की लोकेशन का पता लगाने के लिए अमेरिका के जीपीएस की जरूरत पड़ी थी तब अमेरिका ने मदद से साफ इंकार कर दिया और तब हिंदुस्तान ने ठाना था कि वे अब अपना जीपीएस बनाकर रहेगा। आज भारत उन चुनिन्दा देशों में शामिल है, जिनके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। इसी तरह एक दौर ऐसा भी था जब भारत को रूस ने अमेरिका के दबाव में आकर क्रायोजेनिक रॉकेट टेकोनोर्लॉजी देने से मनाकर दिया था। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ना सिर्फ़ स्वदेशी तकनीकि विकसित की बल्कि आज इसकी मदद से एक साथ दर्जनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ भारत लैबल कॉमर्शियल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरा है। चंद्रयान-3 की उपलब्धि से निश्चित तौर पर देश में अंतरिक्ष के लिए विदेश निवेश का आकर्षित होगा। भारत अमेरिका सहित अन्य देशों की तुलना में बेहद कम कीमत पर सैटेलाइट लॉंचिंग का बेताज बाइशह्र बन चुका है।

राय

संसद में सियासी जमाखोरी

इस अविश्वास ने संसद की भाषा और सदन की मर्यादा को अवश्य ही जनता के सामने बेनकाब कर दिया। जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते-कहते भारत को पारंगत करते थे, वहाँ अविश्वास प्रस्ताव ने कुछ तो स्तर और सारांश गिरा दिया। संसदीय बहस के इतिहास में क्रिकेट के चौके-छक्के मारने का सरकारी पक्ष नाद कर सकता है या उस नारेबाजी का अभिनंदन करें जिसे प्रधानमंत्री स्वयं आहूत करते रहे। संसद के भीतर सियासी नफरतों के इतने पल तो रहे हैं कि अगर देश चारित्रिक या नैतिकता के हिसाब से डूबना चाहे, तो तसल्ली से डूब सकता है। क्या यह राष्ट्रीय मंचन था या राष्ट्रीय मंचन, जहां देश की फटेहाली अपने आवरण को सिल पाई या बहस किसी द्रौपदी को दरबार में ढूंढ रही थी। वहां मुग़लते थे, मुचलके भी थे, लेकिन कोई निर्दोष साबित नहीं हो पाया। अभी तक मणिपुर कहीं मणिपुर में सिसक रहा था, लेकिन देश ने लोकतंत्र की छत के नीचे उसे बिलखते देखा, तो मंजर इनका भी था, उनका भी कम्परा था। वहां किसानों देखा कि बाहर टमाटर की कीमत से हर मतदाता के गाल लाल हो चुके हैं। वहां किसने गौर किया कि देश में पढ़ने के गुनाह से पीढियां बेरोजगार हो गईं। हम यह तो न देखना चाहते थे और न ही सुनना कि जमाखोरी भी हमारी नजरों के सामने, लोकतंत्र के चीरहरण के बीच हमें चुनाव के मजारे दिखाती रही। हमें मालूम हो गया कि देश की सबसे बड़ी जरूरत चुनाव है और यह साबित भी हो गया कि अब सरकार ही चुनाव है। सरकार जब भी बोलती है तो चुनाव बोलती है। आखिर किस चुनाव को सत्य मानें। वह जो हमारे जैसे मतदाताओं के भ्रम बढ़ा देता है या हमें भ्रम में रहना सिखा देता है। हम संसद के लिए मकड़ी हो जाएं या संसदीय बहस के मकड़जाल में घिनौना सन्न कर जाएं। हम भारतीय कर भी क्या सकते, यहां तो भारत किसी के हिस्से में आ रहा है और ‘इंडिया’ परेशान दिखाई दे रहा है। हमने आजादी को जिन निगाहों से देखा, आज देश भी यह समझ नहीं पा रहा कि चुनाव में निजात पाएं भी तो किससे। जो यहां हैं, कल वहां होंगे और जो वहां होंगे उन्हें पवित्र बताया जाने की व्यवस्था हो गई। आखिर कब तक हम अतीत के इस स्तंभ के लिए मकड़ी हो जाएं या संसदीय देखेंगे और कब एक ही भाषण और एक ही मुद्दे का रिपीट टेलिकास्ट देखते रह जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव एक फेरी लगा गया और संसद में कोई देश के एक सौ चालीस करोड़ लोगों की खरीददारी में लग गया। वहां बहस में न पक्ष और न विपक्ष, बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराएं बिक रही थीं। मीडिया भी इस खरीददारी में यही देखता रहा कि क्या उसका ‘स्वामी’ बहुत कुछ खरीदकर जीत गया। यह जीत अगर मीडिया को मुबारक लगती है, तो लोकतंत्र के इस स्तंभ के लिए मकड़ी हो चुके हैं और रीढ़ की वफादारी ने खरीद लिया है। आखिर आम जनता को अगर संसद की अविश्वास फिल्ट्र पसंद नहीं आई, तो वह इस शिकायत को अपना भाग्य मान ले, क्योंकि इससे बेहतर होने की उम्मीद में देश की परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रहीं। क्या संसद से बड़े प्रश्न और मजमून अब सडक पर आएंगे और अगर ऐसा होता है, तो जनता का मत ही बताएगा कि किसका विश्वास-किसका अविश्वास है उसे।

‘एक देश एक चुनाव’ विचार का विरोध करने की बजाय इससे देश को होने वाले लाभ को देखें

प्रो. संजय द्विवेदी

सिर्फ़ खर्च ही नहीं, बल्कि अन्य कई दृष्टि से भी ‘एक देश एक चुनाव’ का विचार काफी फायदेमंद है। इसमें प्रशासनिक तंत्र और सुरक्षा बलों पर बार-बार पड़ने वाला बोझ कम होगा, जिससे वे चुनावी गतिविधियों से बचा समय दूसरे उपयोगी कामों को दे सकते हैं। अब जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में ‘एक देश एक चुनाव’ पर विचार हेतु केंद्र सरकार ने एक समिति बना दी गई है, तब यह मुद्दा बहुत विचारणीय हो गया है। स्वस्थ, टिकाऊ और विकसित लोकतंत्र वही होता है, जिसमें विविधता के लिए भरपूर जगह होती है, लेकिन विरोधाभास नहीं होते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्योन्मुखी दृष्टि वाले नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत धीरे-धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ‘एक देश-एकटेक्स’ की सफलता ने इस बात को सही साबित किया है। अब तक देश के लगभग एक तिहाई राज्यों में लागू हो चुके ‘एक नेशन-एक राशन’ कार्यक्रम के ऐसे ही सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इसी प्रकार, एक देश-एक कानून (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू किए जाने के विचार को भी जनता के एक विशाल वर्ग का अपार समर्थन मिल रहा है। ‘एक देश-एक चुनाव’ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक नीतिगत उपक्रम है। इसे समझने के लिए हमें चुनाव की प्रक्रिया को समझना होगा। हमारे देश में केंद्र और सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र और सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें कार्य करती हैं। इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। ये कार्यकाल, किसी भी महीने पूरा हो सकता है। जब किसी निर्वाचित सरकार का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उस राज्य में अथवा केंद्र में एक निर्धारित अवधि के अंदर नए चुनाव कराना आवश्यक होता है, ताकि वहां नई सरकार गठित की जा सके और देश और उस प्रदेश का काम फिर से सुचारु ढंग से चलना सुनिश्चित किया जा सके। चुनावों की प्रक्रिया को निर्बाध व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए, काफी बड़े तंत्र व खर्च की आवश्यकता होती है। जितने ज्यादा चुनाव, उतनी ही ज्यादा व्यवस्था। 2023 को ही लें। इस साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम समेत देश के दस राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं (इनमें से कुछ राज्यों में इस साल चुनाव हो चुके हैं)। इनमें कितने समय, धन और व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऊपर से, इन चुनावों के खत्म होते-

होते लोकसभा चुनावों की गहमागहमी शुरू हो जाएगी। अब सोचिए कि अगर इन राज्यों के और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था की जा सके तो कितना देश का कितना समय और धन बचेगा।

आज अगर हम देश के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें, तो पायेंगे कि हर वर्ष देश को कोई न कोई हिस्सा चुनावमय बना रहता है। लेकिन, शुरुआत में ऐसा नहीं था। देश के पहले आम चुनावों से लेकर अगले पंद्रह सालों तक, 1952, 1957, 1962, 1967 में चार बार लोकसभा चुनाव हुए और हर बार राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी इनके साथ-साथ ही करवाए गए। लेकिन, जब 1968-69 में अलग-अलग कारणों से कुछ राज्यों की विधानसभाएं उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही भंग कर दी गईं, तो यह सिलसिला बाधित हो गया। यहां तक कि पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले ही करवा लिए गए। चौथी लोकसभा का कार्यकाल 1972 तक था, लेकिन आम चुनाव इसकी पूरा होने से पहले ही 1971 में करा लिए गए। इससे समझा जा सकता है कि अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव और आम चुनाव एक साथ आयोजित कराने की बात की जा रही है तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जिस पर आपत्ति की जानी चाहिए। लेकिन, जब भी केंद्र में सत्तासीन एनडीए सरकार, एक बार फिर इस व्यवस्था की बहाली की बात करती है तो विपक्ष इस तरह मुखर हो उठता है कि जैसे उसे किसी भी हाल में यह नहीं होने देता है। भाजपा विरोधी कुछ दल इस भाजपा का ‘सत्ता का केंद्रीकरण करने की योजना’ कहकर इसका विरोध जारी रखे हैं, जबकि सच तो यह है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ की अवधारणा काफी पुरानी है। इस विषय पर संविधान समीक्षा आयोग, विधि आयोग, चुनाव आयोग और नीति आयोग जैसे प्रभावशाली संस्थानों की राय भी काफी सकारात्मक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में राज्ग सरकार, राष्ट्रहित में इस विचार को और अधिक लटकाए न रखकर एक ठोस व साकार रूप देना चाहती है।

25 साल से जारी है विचार

विशेषज्ञ लंबे समय से ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ पर अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं। वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने में इस साल चुनाव हो चुके हैं। रिपोर्ट का एक पूरा अध्याय इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की इस रिपोर्ट को देश में राजनीतिक प्रणाली के कामकाज पर अब तक के



सबसे सटीक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। मजबूत केंद्र एवं शक्तिशाली नेतृत्व के प्रबल पक्षधर, तत्कालीन गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इसे राजनीतिक स्तर पर प्रमुखता से उठाया था। वर्ष 2003 में, अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को लेकर भाजपा की इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता, पार्टी के 2014 और 2019 के घोषणापत्रों में भी देखी जा सकती है। दूसरी बार सत्ता संभालने के महज एक ही महीने बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2019 को इस पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसके लिए आमंत्रित 40 दलों में से 21 दलों के नेता इस विमर्श में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रखी गई इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया, जिससे इस मुद्दे पर आम सहमति बनाई जा सके और इसके काम करने के तरीकों की व्यवहारिकता और संभावनाओं को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा सके।

समय की मांग है ‘एक देश, एक चुनाव’

इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि राजकोष पर पड़ने वाले चुनावी खर्च के बोझ को कम से कम किया जाए, जो पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ता ही गया है। इसके अलावा थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद होने वाले चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू हो जाने से बहुत सारे विकास कार्य और जनहित कार्यक्रम बाधित होते हैं, इससे भी बचा जा सकेगा।

अगर हम खर्च की ही बात करें तो पिछले पैटर्न को देखते हुए हम पाएंगे कि पहले आम चुनावों से



लेकर पिछले आम चुनावों तक उम्मीदवारों की संख्या करीब पांच गुना बढ़ी है, लेकिन चुनावों पर आने वाला खर्च पांच हजां गुना से भी ज्यादा हो गया है। 1951-52 में जब पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तो इनमें 53 राजनीतिक दल चुनावी समर में उतरे थे। इन चुनावों में 1874 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और खर्च आधा कुल 11 करोड़ रुपए। अब 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हैं। इनमें कुल 9000 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और खर्च था लगभग 60 हजार करोड़ रुपए। यानि हर लोकसभा क्षेत्र पर औसतन 110 करोड़ का खर्च। जबकि 2014 के आम चुनावों पर इसका आधा ही यानी लगभग 30 हजार करोड़ रुपए खर्च आया था। अब देश में विधानसभा सीटों की बात करते हैं। सभी राज्यों में कुल मिलाकर विधानसभा की चार हजार से अधिक सीटें हैं। मोटे-मोटे तौर पर एक लोकसभा क्षेत्र में करीब आठ विधानसभा सीटें आती हैं। अगर हम 2019 के आम चुनावों के खर्च को विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह लगभग 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाली आठ विधानसभा सीटों के लिए दो अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। ऐसे में यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, और इसके अलावा 15 करोड़ रुपए प्रति विधानस

मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल को लेकर आई बड़ी खबर, सोमवार को शेयरों पर दिखेगा सीधा असर

परिवहन विशेष न्यूज

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने मुकेश अंबानी की नई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के लिए सर्किट सीमा को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर बाजार में बीते 21 अगस्त को लिस्ट हुए थे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह शेयर अगले सप्ताह 'ट्रेड-टू-ट्रेड' खंड से बाहर हो जाएगा।

नई दिल्ली। देश के प्रमुख इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने मुकेश अंबानी की नई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services) की सर्किट लिमिट में बदलाव कर दिया है। बीएसई ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की अलग हुई गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के लिए सर्किट सीमा को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। बीएसई द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, नई बड़ी हुई सर्किट लिमिट सोमवार यानी 4 सितंबर 2023 से लागू होगी। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि एक सत्र में कंपनी के शेयर के भाव में



एक निश्चित सीमा से अधिक का उतार-चढ़ाव नहीं आए।

इसके अलावा बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह शेयर अगले सप्ताह 'ट्रेड-टू-ट्रेड' खंड से बाहर हो जाएगा। जियो फाइनेंशियल के अलावा रेलटेल और इंडिया पेट्रोलसाइंड्स सहित नौ कंपनियों के लिए मूल्य दायरे को संशोधित कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। किसी

शेयर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रण में रखने के लिए बीएसई द्वारा 'सर्किट' व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक दिन में किसी शेयर में अधिकतम उतार-चढ़ाव की सीमा है। इसके अलावा, एक सितंबर को जियो फाइनेंशियल के शेयर को बेंचमार्क सेंसेक्स सहित सभी बीएसई सूचकांकों से हटा दिया गया था। मूल कंपनी रिलायंस

इंडस्ट्रीज से अलग होने के कारण जियो फाइनेंशियल के शेयर 21 अगस्त को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुए थे। पहले कंपनी के शेयर को 24 अगस्त को सूचकांकों से हटाया जाना था। बाद में इसे 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, इसके लगातार निचले सर्किट को छूने की वजह से एक्सचेंजों से इसे हटाने में और देरी हुई।

पिछले तीन कारोबारी सत्रों में कंपनी के शेयर में तेजी आई है और इसने ऊपरी सर्किट सीमा को छुआ है। पिछले महीने कंपनी की सालाना आमसभा में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की थी कि जियो फाइनेंशियल बीमा क्षेत्र में उतरेंगी और यह जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश करेगी।

खत्म होने वाला है इंतजार, इस दिन आएगा टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ, जान लीजिए



टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ बाजार में जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 9.57 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी। इसमें 8.11 करोड़ रुपये के शेयर टाटा मोटर्स अपने हिस्से के बेचेगे। सेबी से आईपीओ को अप्रूवल मिल चुका है।

नई दिल्ली: दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) के टाटा ग्रुप की एक और कंपनी का आईपीओ (IPO) बाजार में जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। टाटा ग्रुप का ये आईपीओ करीब 20 वर्षों के बाद आ रहा है। इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। यह आईपीओ टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी (Tata Technologies IPO) का होगा। टाटा टेक्नोलॉजी (Tata Technologies IPO) ने इस साल मार्च महीने में अपना आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाजार नियामक सेबी (SEBI) से टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ (Tata Technologies IPO) को एक

महीना पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। सेबी से आईपीओ (Initial Public Offering) के लिए अप्रूवल मिलने के बाद से ही निवेशकों के बीच में इसे लेकर काफी उत्साह है। जानकारों के मुताबिक, आईपीओ को सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी इसके लॉन्च डेट के बारे में एक से दो महीने तक का समय ले सकती है। इसके बाद ही वह आईपीओ के प्राइस बैंड का ऐलान करेगी।

क्या है GMP ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक, कंपनी (Tata Technologies) इस आईपीओ (IPO) के माध्यम से करीब 9.57 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी। इसमें से 8.11 करोड़ रुपये के शेयर टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपने हिस्से के बेचेगी। वहीं बाकी शेयरों में अलका टीसी होल्डिंग्स 97.2 लाख और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 1 अपनी होल्डिंग्स से 48.6 लाख शेयरों को बेचेगी। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह आईपीओ अभी सौ रुपये के जीएमपी पर कारोबार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी 280 से 320 रुपये के बीच तय कर सकती है।

इनसाइड

कार्यकाल बढ़ाए बिना कैसे कम करें Home Loan का EMI, क्या है इसका आसान तरीका?

होम लोन का बोझ निश्चित रूप से एक लेनदार के लिए एक बड़ा खर्च है। हर कोई सबसे कम ब्याज दर पर लोन खरीदना चाहता है और निर्माण लोन से जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता है। हालांकि होम लोन लेने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि पिछले साल ब्याज दरें बढ़ गई हैं। पढ़िए बिना कार्यकाल बढ़ाए होम लोन की ईएमआई कैसे कम कर सकते हैं।

नई दिल्ली: होम लोन का बोझ निश्चित तौर पर एक लोन लेने वाले ग्राहक के लिए बड़ा खर्च है। सभी लोग लोन को कम से कम ब्याज दर पर खरीदना चाहते हैं और जल्द से जल्द इस होम लोन से छुटकारा चाहते हैं। लेकिन होम लोन लेने वाले ग्राहक पिछले एक साल में ब्याज दरों में भारी वृद्धि के कारण वे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। होम लोन के लिए ग्राहकों की सबसे पसंदीदा अवधि 20 साल वाले में लोन की ईएमआई में 22 प्रतिशत का उछाल देखा गया है। इस अवधि के लिए ब्याज दरें 7 प्रतिशत से बढ़कर 9.5 प्रतिशत तक हो गई हैं। 18 जून को रिजर्व बैंक की मोनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ा था। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होम लोन की ईएमआई कटवाने का आसान तरीका क्या है।

जब अपने बीमार कुत्ते के लिए रतन टाटा ने टुकरा दिया था ब्रिटेन के शाही परिवार का अवार्ड, फिर भी

परिवहन विशेष न्यूज

जब अपने बीमार कुत्ते के लिए रतन टाटा ने टुकरा दिया था ब्रिटेन के शाही परिवार का अवार्ड, फिर भी जीत लिया अंग्रेजों का दिल

नई दिल्ली: देश में उद्योगपति तो कई हैं, कई कारोबारी घराने भी हैं, कईयों ने देश की इकॉनमी को बढ़ाने का काम किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन जब नाम रतन टाटा (Ratan Tata) का आता है तो अपने आप दिल से उनके लिए सम्मान की भावना आ जाती है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हैं, देश के लिए वो एक प्रेरणा है, युवाओं के लिए उनके Idol हैं। इसकी वजह भी है, क्योंकि रतन टाटा ने केवल अपना कारोबार नहीं बढ़ाया बल्कि समाज के लिए काम करते रहे। यहीं तो उनकी खासियत है, जो लोगों के मन में उनके लिए प्यार और सम्मान भर देता है। सिर्फ ईसान ही नहीं रतन टाटा के मन में बेजुबान जानवरों के लिए भी प्यार भरा है। रतन टाटा जिसे अपना मानते हैं, उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं।

बेजुबानों के लिए रतन टाटा का प्यार

रतन टाटा को जानवरों से बहुत प्यार है। अक्सर वो अपने सोशल



मीडिया पेज पर जानवरों के लिए लिखते भी रहते हैं। उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए घर भी बना रखा है। बिजनेसमैन और कॉलमनिस्ट सुहेल सेठ (Suhel Seth) ने भी रतन टाटा की ज़िन्दगी से जुड़ा एक खास किस्सा शेयर करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने कुत्ते के लिए ब्रिटेन के शाही परिवार की ओर से मिलने वाले अवार्ड को टुकरा दिया। उन्होंने अवार्ड फंक्शन में आने से इंकार कर दिया।

किंग चार्ल्स रतन टाटा को सम्मानित करना चाहते थे

बिजनेसमैन और कॉलमनिस्ट सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में बताया कि

ब्रिटेन से प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को सम्मानित करना चाहते थे। 16 फरवरी 2018 को उन्हें बकिंगम पैलेस में बुलाकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि मैं 2 फरवरी को ही लंदन पहुंच गया था। फ्लाइट से उतरा तो रतन टाटा के 11 मिस्ट कॉल थे। उन्होंने जब कॉल बैक किया तो टाटा वे उनसे कहा कि उनके पालतू कुत्ते टैगो और टैटो में से एक की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो उसे छोड़कर लंदन नहीं आ सकते। सुहेल सेठ ने रतन टाटा को समझाया कि ये कोई आम अवार्ड नहीं है। प्रिंस चार्ल्स

खुद इस अवार्ड फंक्शन को ऑर्गनाइज करवा रहे हैं, लेकिन रतन टाटा नहीं आए।

प्रिंस चार्ल्स ने की तारीफ

अपने बीमार कुत्ते को छोड़कर रतन टाटा नहीं गए। उन्होंने ब्रिटेन के शाही परिवार के अवार्ड से बढ़कर अपने पालतू कुत्ते को महत्व दिया। वो चाहते तो किसी नौकर के भरोसे उसे छोड़ सकते थे, लेकिन रतन टाटा ने ऐसा नहीं किया। जब यह बा प्रिंस चार्ल्स को पता चला तो नाराज होने के बजाए उन्होंने रतन टाटा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रतन टाटा की इसी आदत की वजह से आज टाटा समूह इस मुकाम पर है।

सोशल मीडिया पर दूसरों को बेवकूफ बना फिनफ्लुएंसर्स कमा रहे करोड़ों रुपये, अब सेबी उठाने जा रहा ये कदम

परिवहन विशेष न्यूज

युवाओं की ट्रेडिंग में बढ़ती संख्या को देखते हुए कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ट्रेडिंग के कोर्स बेचकर बंपर कमाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन फिनफ्लुएंसर की बाढ़ सी आ गई है। अब सेबी इन्हें पंजीकृत कराने के साथ दिशानिर्देशों का पालन कराने की योजना बना रहा है।

नई दिल्ली: देश में बड़ी संख्या में युवा अब ट्रेडिंग की ओर जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद इसमें काफी इजाफा हुआ है। युवाओं को लगातार बढ़ती संख्या को देख सोशल मीडिया पर फाइनेंसियल इन्फ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर भी काफी एक्टिव हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सलाह देने वाले एक्सपर्ट्स की बाढ़ सी आ गई है। इनमें से



ज्यादातर के पास कोई डिग्री भी नहीं है। अब एक नया ट्रेड सामने आया है। इसमें कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर में खुद ट्रेडिंग में नुकसान उठाने के बाद उसे कवर करने के लिए युवाओं को फ्यूचर एंड ऑप्शन के कोर्स बेचकर पैसे वसूल रहे हैं। अब सेबी इन फिनफ्लुएंसर पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है।

निवेशकों तक सटीक और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने के लिए बाजार नियामक सेबी वित्तीय 'इन्फ्लुएंसर' पर अंकुश लगाने जा रहा है। वित्तीय इन्फ्लुएंसर डिजिटल मीडिया, चैनल आदि के माध्यम से लोगों को निवेश के बारे में सलाह देते हैं। दरअसल ऐसा पता चला था कि ये वित्तीय इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के

लिए 7.5 लाख रुपये तक लेते हैं और अपनी राय से लोगों के वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं।

हालांकि, अब इन्हें नियामक के दायरे में आना होगा, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) इनकी तेजी से बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। आनंद राठी वेलथ के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) फिरोज अजीज ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सेबी का प्रस्तावित कदम यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों को सटीक और निष्पक्ष जानकारी मिले। इससे उन्हें धोखाधड़ी से बचाने में भी मदद मिलेगी।

प्रस्ताव के तहत वित्तीय इन्फ्लुएंसर को सेबी के पास अपना पंजीकरण कराना होगा, और निवेशकों को सटीक और निष्पक्ष जानकारी मिले। इससे उन्हें धोखाधड़ी से बचाने में भी मदद मिलेगी।

प्रस्ताव के तहत वित्तीय इन्फ्लुएंसर को सेबी के पास अपना पंजीकरण कराना होगा, और निवेशकों को सटीक और निष्पक्ष जानकारी मिले। इससे उन्हें धोखाधड़ी से बचाने में भी मदद मिलेगी।

पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस में कैसे लगी आग, जांच में जुटे रेलवे

दक्षिणी रेलवे ने लखनऊ से रामेश्वरम जाने वाली पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस के प्राइवेट कोच में लगी आग की जांच शुरू की है। यह घटना नौ यात्रियों की मौत के साथ घटी थी। रेलगाड़ी के डिब्बे में आग कैसे फैली इसकी जांच के लिए कम से कम एक महीने का समय लगेगा। हादसे के शिकार नौ लोगों के शव लखनऊ ले जाए गए हैं।

नई दिल्ली: नई दिल्ली: पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस के प्राइवेट कोच में लगी आग से कई सवाल उठने लगे हैं। कोच में लगी आग लापरवाही का नतीजा है या फिर कुछ और। घटना में हुई लापरवाही का पता लगाने के लिए दक्षिणी रेलवे ने अपनी जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के प्राइवेट कोच में अचानक आग लग गई। इस हादसे में नौ यात्रियों की मौत हो गई। दक्षिणी क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा आयोग ए.एम. चौधरी ने यहां रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लगने की घटना की रविवार को जांच शुरू की। चौधरी ने एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि फिलहाल उन्हें इसमें किसी तरह की साजिश नजर नहीं आती



है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन यात्रियों से पूछताछ की, जिनका यहां इलाज किया गया था। चौधरी ने कहा कि उन्होंने उनके बयान दर्ज किये कि यार्ड में खड़े डिब्बे में आग कैसे फैल गई। उन्होंने कहा कि जांच पूरी करने और अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा। उन्होंने यहां रेलवे यार्ड में खड़े उस डिब्बे का निरीक्षण किया, जिसमें शनिवार को आग लग गई थी। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के डिब्बे में शनिवार तड़के आग लग गई थी जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी और आठ अन्य झुलस गये थे। हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार, हादसे के शिकार नौ लोगों के शवों को आज हवाई मार्ग से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले जाया गया।

